

मुख्य समाचार :-

- स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं समीक्षा की। कहा— प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सरकार की प्राथमिकता है।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
- देहरादून जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटा प्रशासन। कालाबाजारी रोकने के लिए कई जगह छापेमारी।
- और, प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 29 केन्द्र बनाए गए। 27 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेगा मूल्यांकन कार्य।

स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपचाराधीन मरीजों से मुलाकात की और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से संवाद कर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में बेहतर समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, ताकि प्रत्येक मरीज को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। श्री उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रदेश में पलायन का मुख्य कारण बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक बुनियादी सुविधाओं में मजबूती नहीं आएगी, तब तक पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को राज्य की प्राथमिकता बताते हुए विभाग में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने पर विशेष बल दिया।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड, एपिडा या अन्य उपलब्ध योजनाओं के माध्यम से इस परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, ताकि स्थानीय कृषकों को अपनी उपज के संरक्षण और विपणन में सुविधा मिल सके। कृषि मंत्री ने देहरादून में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य और केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागीय कार्यों की स्थिति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के हित में कृषि और बागवानी से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए तथा जन उपयोगी योजनाओं का निर्माण कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाए। बैठक में औद्योगिकी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य में स्थापित आईटीबीपी बटालियनों के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत सीमांत क्षेत्रों के कृषकों द्वारा उत्पादित ताजे फल और सब्जियों का विक्रय किया जाएगा। इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों में बागवानी कर रहे किसानों को स्थानीय बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।

कुंभ तैयारी

मेलाधिकारी सोनिका ने हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को सभी गतिमान कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेलाधिकारी ने कुंभ मेला के लिए की जाने वाली अस्थायी व्यवस्थाओं से जुड़े सभी कार्यों के आगणन शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक आगणन सही, तर्कसंगत व औचित्यपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेला से जुड़े कार्यों की प्रगति की सघन समीक्षा के लिए प्रत्येक पखवाड़े में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं के अधीक्षण अभियंता या अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग कर प्रगति का ब्यौरा देंगे। मेलाधिकारी ने कार्यस्थलों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों को निरंतर सुचारु बनाए रखने और श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति और कार्य प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया। अपर मेलाधिकारी और उप मेलाधिकारी को भी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

अग्निकांड

उत्तरकाशी जिले में मोरी तहसील के ग्राम फिताड़ी में आज अचानक आग लगने से पांच से छह आवासीय भवन इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

रसोई गैस आपूर्ति

देहरादून जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं, ताकि गैस की कालाबाजारी को रोका जा सकें। जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने कहा कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग करने में कोई समस्या न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

मूल्यांकन केंद्र

प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आगामी 27 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए राज्य में कुल 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। रामनगर स्थित उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभापति डॉ. मुकुल कुमार सती की अध्यक्षता में आयोजित मूल्यांकन पूर्व बैठक के बाद परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमलटी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य के लिए हाईस्कूल में एक हजार 457 परीक्षक, 160 उप प्रधान परीक्षक और 320 अंकक्षकों, जबकि इंटरमीडिएट में एक हजार 298 परीक्षक, 143 उप प्रधान परीक्षक और 284 अंकक्षकों की नियुक्ति की गई है।

बिहार दिवस

लोक भवन में कल बिहार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड में रह रहे बिहार के लोगों सहित राज्य में कार्यरत शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बिहारी महासभा की ओर से बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि बिहार की धरती ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति और इतिहास की अनमोल धरोहर रही है। उन्होंने कहा कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को सशक्त बनाने के लिए सभी राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं को जानना और अपनाना आवश्यक है। इस प्रकार के आयोजन न केवल विभिन्न राज्यों

के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी सुदृढ़ करते हैं।

खाद्यान्न वितरण

टिहरी के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने बताया कि राशन कार्डधारकों को माह फरवरी के खाद्यान्न वितरण की अवधि आगामी 31 मार्च तक विस्तारित की गई है। साथ ही मार्च माह के खाद्यान्न वितरण की अवधि भी 31 मार्च तक रहेगी। उन्होंने सभी राशन कार्डधारकों से अनुरोध किया कि जिले के कार्ड धारक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से फरवरी और मार्च माह का खाद्यान्न 31 मार्च तक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करते समय अपने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर स्थापित ई – पॉस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने का भी अनुरोध किया है।

मंजूरी

प्रदेश में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों की घेरबाड़ के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सहायता किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

निर्यातित उत्पाद शुल्क

केंद्र सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के तहत दर और मूल्य सीमा को कल से बहाल कर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पश्चिम एशिया में व्यापार व्यवधानों के बीच निर्यातकों को समर्थन देने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि बहाल दरें वही होंगी जो इस वर्ष 22 फरवरी से लागू हुई थीं।

तपेदिक दिवस

आज विश्व तपेदिक दिवस है। इसका उद्देश्य तपेदिक के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करना है।

मुख्य समाचार एक बार फिर—

- स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं समीक्षा की। कहा— प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सरकार की प्राथमिकता है।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
- देहरादून जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटा प्रशासन। कालाबाजारी रोकने के लिए कई जगह छापेमारी।
- और, प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 29 केन्द्र बनाए गए। 27 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेगा मूल्यांकन कार्य।